तेल पर तनाव

अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खींचतान बहुत जल्दी भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर नकारात्मक असर डाल सकती है. अमेरिका ने भारत समेत आठ देशों को दी गयी ईरान से तेल आयात की छूट की अवधि को नहीं बढ़ाने की घोषणा की है. छह माह की यह छूट मई के प्रारंभिक दिनों में समाप्त हो जायेगी. सऊदी अरब और इराक के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता है. साल 2018-19 में यह खरीद 23.5 मिलियन टन रही थी. आयात बंद करने या कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है तथा भारत ने इस चिंता से अमेरिका को अवगत करा दिया है. कच्चे तेल की हमारी जरूरत का करीब 85 फीसदी और प्राकृतिक गैस का 34 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा होता है. ईरान से बेहतर रिश्ते होने के कारण भारत को भुगतान करने के लिए 60 दिन का समय मिलता है तथा ढुलाई और बीमा का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के रुझान हैं. ऐसे में हमारे आयात का खर्च और व्यापार घाटा में बढ़ोतरी हो सकती है. सामान्य हिसाब यह है कि यदि दाम में प्रति बैरल एक डॉलर की बढ़त होती है, तो हमारे ऊपर 10,700 करोड़ रुपये सालाना का बोझ बढ़ जायेगा. हाल के दिनों में कीमतों के बढ़ने से हमारा रुपया भी कमजोर हुआ है. रुपये के मूल्य में कमी से भी व्यापार घाटा बढ़ जाता है. हालांकि, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से आयात के विकल्प हैं, लेकिन इसे तुरंत अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा. वैश्विक स्तर पर 40 फीसदी तेल उत्पादित करनेवाले तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा आपूर्ति में कटौती का सिलसिला भी जारी है. ईरान के अलावा अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी पाबंदी लगाया है. इन कारकों से तेल के बाजार का रुख अस्थिर है. भारत ने वेनेजुएला से अप्रैल, 2018 और जनवरी, 2019 के बीच अपनी तेल जरूरत का करीब 6.4 फीसदी हिस्सा खरीदा है. इस पर अमेरिका ने आपत्ति जतायी है. यदि भारत ईरान और वेनेजुएला से तेल नहीं लेता है, तो उसे लगभग 17.6 फीसदी तेल दूसरे देशों से लेना होगा. बाजार से दोनों देशों के हटने से आपूर्ति बाधित होगी और कीमतों में उछाल आयेगा. यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का आयात 2016-17 की तुलना में 2017-18 में 25 फीसदी बढ़ गया था. ऐसे में घरेलू उत्पादन को भी तेज करने की जरूरत है. ईरान की आर्थिकी पर अमेरिका के शिकंजा कसने से चाबहार बंदरगाह परियोजना पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो भारत के रणनीतिक हितों के साथ क्षेत्रीय वाणिज्य-व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है. अभी इस परियोजना का एक ही चरण पूरा हो सका है तथा इसे पाकिस्तान में चीन के सहयोग से बन रहे ग्वादर बंदरगाह के बरक्स ठोस पहल माना जाता है. समाधान के लिए भारत को सीधे अमेरिका से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तनावों और प्रतिबंधों से इतर कूटनीतिक कदम उठाया जाना चाहिए.

यदि भारत ईरान और वेनेजुएला से तेल नहीं लेता है, तो उसे लगभग 17.6 फीसदी तेल दूसरे देशों से लेना होगा. बाजार से दोनों देशों के हटने से आपूर्ति बाधित होगी और कीमतों में उछाल आयेगा.

दलबदलुओं पर निर्भर होती राजनीति

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla
@newindianexpress.com

सफल नेतागण सिर्फ अपने वारिसों को गढ़कर ही अपनी विरासत टिकाऊ बना पाते हैं. चूंकि आदर्श रूप में किसी सियासी पार्टी की सक्रियता किसी खास विचारधारा से ऊर्जा पाती है, इसलिए नेताओं की विरासत पार्टी में नये झंडाबरदारों की लगातार भर्ती पर ही निर्भर होती है. पर लोकसभा के लिए वर्ष 2019 के संग्राम ने लगभग सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों का वैचारिक दिवालियापन उजागर कर दिया है. हालांकि उनके शीर्ष पर बड़े-बड़े नेता बैठे हैं, पर वे अपने ही काडर से जीतनेवाले उम्मीदवार तलाश पाने में असमर्थ हैं. वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को ऐसे व्यक्तियों की खोज है, जिनका बाहुबल, धनबल अथवा उनका सामुदायिक बल, न कि उनकी वैचारिक संबद्धता, उनकी जीत पक्की करता हो. भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टियां जमीनी प्रचार की अपेक्षा दूसरी पार्टियों के ऐसे उम्मीदवारों की खरीद पर ज्यादा धन खर्च कर रही हैं. विचारधारा मर चुकी. व्यक्ति की अहमियत अमर हो चली है.

यह एक विडंबना ही है कि 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस और 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा लोकसभा की कुल सीटों के लिए 542 उम्मीदवार भी नहीं तलाश सकतीं और दोनों में से कोई इन चुनावों के कुल सात चरणों में दो के संपन्न हो जाने के बाद भी अपने उम्मीदवारों की संपूर्ण सूची प्रकाशित नहीं कर सकी है. स्पष्ट है कि मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियां भी विचारधारा अथवा अपने प्रदर्शन की बजाय सिर्फ गठबंधनों तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप से प्रभावशील उम्मीदवारों की ही आस लगा रखी हैं. वरना कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के लिए इस बात का क्या औचित्य हो सकता है कि वे दिल्ली तथा हरियाणा के लिए अपने सभी उम्मीदवार ससमय घोषित नहीं कर सके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वर्ष 2014 के अपने वायदों की भरपाई पर गर्व प्रकट करते हुए बड़ी-बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं. इसी तरह कांग्रेस भी सत्ता में आने पर न्याय करने के प्रण प्रकट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही. पर दोनों में से किसी को भी यह यकीन नहीं कि उनके आजमाये और वफादार कार्यकर्त्ता अपनी व्यक्तिगत स्वीकार्यता तथा विश्वसनीयता के बूते जीत सकते हैं. केरल में तो भाजपा अपनी चुनावी संभावनाओं की बेहतरी के लिए कट्टर मार्क्सवादियों का और कांग्रेस संघी-भाजपा पृष्ठभूमि के दलबदलुओं का भी स्वागत करने को तैयार है.

पिछले दो दशकों के दौरान पार्टी झंडों के रंग भले ही न बदले हों, पर उनके मानव संसाधन में नाटकीय परिवर्तन आ चुका है. चुनावी मौसम में सियासी व्यापार की यह प्रक्रिया और भी तेज हो उठती है. भारत के दो-तिहाई राज्यों से भी अधिक पर शासन करनेवाली भाजपा ने पिछले ही सप्ताह गोरखपुर सीट के लिए कांग्रेस के एक दलबदलू को चुना. यह वही सीट है, जिसका प्रतिनिधित्व यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले पांच कार्यकालों से करते आ रहे थे. इसी तरह, सपा-बसपा महागठबंधन के उम्मीदवार के विरुद्ध उनका जवाब भोजपुरी फिल्मों के पुराने पड़ चुके नायक रवि किशन पर टिका है. वर्ष 2017 के उपचुनाव में विजयी संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार प्रवीण निषाद को अब भाजपा ने अपना लिया और उन्हें संत कबीर नगर से अपना प्रत्याशी बना डाला. पूर्वी यूपी को संघ का गढ़ माना जाता है. फिर भी भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस सीट को भरने हेतु कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सका. सो एक बार फिर वह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विरुद्ध आजमगढ़ से भोजपुरी सिनेमा के ही एक अन्य नायक निरहुआ को उतारने के सिवाय कुछ और न सोच सकी. पूर्व सिने तारिका तथा समाजवादी समर्थक जयाप्रदा को भी इस बार उसने अपना उम्मीदवार बना रामपुर से खड़ा कर दिया.

वर्ष 2019 का यह एक चिंताजनक घटनाक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेतागण भी अपनी जीत के प्रति पक्के न रहते हुए पेशेवर दलबदलुओं से सौदेबाजी को बाध्य हैं.

इससे भी बढ़कर अचरज की बात इसके द्वारा आतंकी अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध उतारना है. भोपाल पारंपरिक रूप से ही संघ के प्रभाव क्षेत्र में रहा है. आजादी के बाद से अब तक 16 लोकसभाओं के लिए संपन्न आम चुनावों में जनसंघ या भाजपा के उम्मीदवार यहां से 10 दफा विजयी हो चुके हैं और उसके उम्मीदवारों ने औसतन 50 प्रतिशत से भी अधिक मत प्राप्त किये हैं. मध्य प्रदेश में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उमा भारती एवं कैलाश जोशी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री कमल नाथ ने दिग्विजय सिंह को यहां से उम्मीदवारी के लिए तैयार कर भाजपा को चकित कर दिया और भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ तथा प्रतिबद्ध नेताओं की दावेदारी उपेक्षित कर साध्वी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाकर अपनी विश्वसनीयता तथा संगठनात्मक कमजोरी ही उजागर कर डाली.

इसी तरह, कांग्रेस एवं अन्य पार्टियां भी बाहरी तत्वों को पटाने में पीछे नहीं हैं. कांग्रेस ने करिश्माई बॉलीवुड अभिनेता और तीन दशकों से भाजपाई रहे शत्रुघ्न सिन्हा का खुशी-खुशी स्वागत किया. समाजवादी पार्टी ने भी सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विरुद्ध लखनऊ से अपना उम्मीदवार बना लिया.

कोई भी राज्य अथवा पार्टी व्यक्तिपूजन संस्कृति का अपवाद नहीं रही. उत्तर-पूर्व में भाजपा के चमत्कारिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करनेवाले असम के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वाशर्मा ने 25 वर्षों तक कांग्रेसी रह 2015 में भाजपा का दमन थामा. संभव है, पश्चिम बंगाल तथा ओड़िशा में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता में भी वृद्धि हुई हो, पर उसके उम्मीदवारों में बड़ी तादाद स्थानीय सत्तारूढ़ पार्टियों से दलबदल कर आये नेता ही हैं. राहुल ने स्वयं भी विलय तथा अधिग्रहण की कला में महारत हासिल कर ली है. राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्थानीय नेताओं को ज्यादा ऊपर न उठने देने की कोशिशों ने बड़ी संख्या में जाति तथा क्षेत्र आधारित पार्टियों को जन्म दिया. कुल लगभग 300 छोटी पार्टियों में से 200 के करीब का जन्म उन व्यक्तियों द्वारा हुआ है, जिन्होंने अधिक लाभ के लिए अपने राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संगठन छोड़ दिये. वर्ष 2019 का यह एक चिंताजनक घटनाक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेतागण भी अपनी जीत के प्रति पक्के न रहते हुए पेशेवर दलबदलुओं से सौदेबाजी को बाध्य हैं. सत्ता की अपनी भूख में वे भविष्य के लिए नैतिक तथा वैचारिक आधार पर एक नये नेतृत्व के पोषण एवं विकास की कला भुला बैठे हैं.

कट्टरता की चपेट में श्रीलंका

डॉ गुलबिन सुल्ताना
रिसर्चर, आईडीएसए
gulbin.sultana@gmail.com

बीते 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में गिरजाघरों और होटलों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने कई बम धमाके किये. सैकड़ों लोगों की जान चली गयी और अनेक घायल हुए. हालांकि, एक आत्मघाती की पहचान की गयी है, लेकिन अभी ठोस जानकारियों का पता चलना बाकी है. दुनिया के लिए नासूर बन चुका आइएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. धमाकों के बाद भी जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किये गये, उससे यह किसी छोटे आतंकी समूह का काम नहीं लग रहा था. जांच अब भी चल रही है और कई चीजों को लेकर सिर्फ अनुमान ही लगाये जा रहे हैं. हमले के बाद दरअसल, श्रीलंका सरकार ने यह आशंका जतायी थी कि इस घृणित कार्य में वहां के एक स्थानीय संगठन नेशनल तौहीद जमात का हाथ हो सकता है. इस उग्रवादी संगठन पर श्रीलंका सरकार को इसलिए शक लाजमी भी है, क्योंकि काफी पहले (बीते 4 अप्रैल को ही) श्रीलंका की आधिकारिक सुरक्षा एजेंसी को इस संबंध में खूफिया सूचना मिली थी कि कोई ऐसा हमला हो सकता है. भारत ने भी श्रीलंका को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा था और आशंका जाहिर की थी कि कोलंबो में अवस्थित भारतीय दूतावास पर हमला हो सकता है. तमाम खूफिया सूचनाओं और एलर्ट के बाद भी इतना बड़ा हमला हो गया और सैकड़ों लोग मारे गये, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी सुरक्षा चूक कही जा सकती है. इससे यह बात तो जाहिर है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने इस एलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया होगा और शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह कई जगहों पर इतने बड़े-बड़े हमले हो सकते हैं. हालांकि, जरा-सी खुफिया सूचना पर भी उन्हें तैयार हो जाना चाहिए था और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर देना चाहिए था. क्योंकि सूरक्षा में चूक का मतलब ही है कि हम कई महत्वपूर्ण जिंदगियों से हाथ धो बैठेंगे.

नेशनल तौहीत जमात को लेकर यह संदेह बलवती होती है कि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलायी होगी. और अब आइएस के जिम्मेदारी ले लेने के बाद यह बात साबित भी हो गयी है.

श्रीलंका में मुस्लिमों की आबादी आठ-नौ प्रतिशत के करीब है. श्रीलंकाई मुसलमान उग्र नहीं होते, इन्हें वहां काफी उदारवादी स्वभाव का माना जाता है. लेकिन, बीते कुछ समय से जिस तरह से पूरे दक्षिण एशिया में कट्टरता बढ़ रही है, जगह-जगह कुछ लोग उग्रवाद का सहारा लेने लगे हैं. श्रीलंका भी इससे अछूता नहीं रहा है और हाल के वर्षों में कुछ लोगों के आइएस में जाने की भी खबरें आयीं. लेकिन यह संख्या दशमलव में है. श्रीलंका में धार्मिक समुदायों के आपसी नोकझोंक के बावजूद कट्टरता कम रही है, लेकिन वहां पर अगर नेशनल तौहीद जमात जैसे संगठनों का उभार हो रहा है, तो यह समझनेवाली बात है कि वहां भी आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं. हालांकि, इस संगठन के बारे में भी किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर इसका काम क्या है. करीब तीन साल पहले श्रीलंका सरकार को इसकी जानकारी मिली थी. दरअसल, उन दिनों श्रीलंका में मुस्लिमों और बौद्धों के बीच तनाव के मामले आते रहे हैं. उस दौरान नेशनल तौहीद जमात ने कुछ बौद्ध स्मारकों को निशाना बनाया था, सिवाय इसके इस संगठन ने किसी हिंसात्मक कार्य को अंजाम नहीं दिया था. इसलिए सरकार ने इसे लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखायी.

किसी भी बड़े हमले के बाद वहां के स्थानीय छोटे-बड़े कट्टर संगठनों की ओर उंगली उठती है कि उनका हाथ हो सकता है. लेकिन, हमारे शोध यह कहते हैं कि एक स्थानीय संगठन तब तक इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सकते, जब तक कि उसके पीछे किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाथ न हो. स्थानीय स्तर पर किसी छोटे संगठन द्वारा आत्मघाती हमले की संभावना बहुत ही कम मानी जाती है. अगर एकबारगी यह मान भी लिया जाये, जैसा कि श्रीलंका की सरकार ने आशंका जतायी थी, कि नेशनल तौहीद जमात ने ही हमला किया होगा, तो भी यह समझना मुश्किल है कि इतने बड़े हमले का जो स्वरूप है, उसे इस छोटे से संगठन ने कैसे तैयार किया? इसलिए नेशनल तौहीद जमात को लेकर यह संदेह बलवती होती है कि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलायी होगी. और अब आइएस के जिम्मेदारी ले लेने के बाद यह बात साबित भी हो गयी है. दरअसल, श्रीलंका में स्थानीय उग्रवादी संगठन आपस में भले एक-दूसरे से लड़-भिड़ लेते हैं, लेकिन वहां की पुलिस व्यवस्था से वे कभी टकराव मोल नहीं लेते हैं. इस बात की अपनी कुछ वजहें जरूर होंगी, जिसका अध्ययन से ही पता चल पायेगा.

यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका में बीते सालों में बौद्धों और मुस्लिमों के बीच तनाव चल रहा था. लेकिन, हमला हुआ गिरजाघरों और होटलों में, वह भी ईसाइयों के पर्व ईस्टर के दिन. इसलिए सवाल उठ रहा था कि श्रीलंका में कोई मुस्लिम संगठन गिरजाघरों पर हमला क्यों करेगा? गिरजाघर ईसाइयों से संबंधित है, तो वहीं उन होटलों में ज्यादातर विदेशी नागरिक मौजूद थे. विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा भारत के नागरिक इस हमले में हताहत हुए हैं. तो मीडिया में आयी खबर के मुताबिक, इसका जवाब यह निकलकर आया है कि जिम्मेदारी लेते हुए आइएस ने न्यूजीलैंड में हुए मस्जिद में हमले का बदला लिया गया है. हालांकि, श्रीलंका सरकार ने इंटरपोल की मदद भी मांगी है और कई अन्य देशों ने भी मदद की पेशकश की है. इसकी बड़ी जांच जरूरी है, क्योंकि तब और भी कई बातें दुनिया के सामने आयेंगी.

आपके पत्र

श्रीलंका सरकार की कठिन चुनौती

श्रीलंका में आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर 290 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हो गये हैं. स्थानीय के अलावे कई अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं. आखिर क्यों नहीं रुक रही है आतंकवादी गतिविधियां और हत्याओं का सिलसिला? जितना इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यह दिन-प्रतिदिन उतना ही बढ़ता जा रहा है. इससे पहले भी भारत के पुलवामा में और न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के मस्जिदों को आतंकियों ने निशाना बनाया था. श्रीलंका सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जब वहां के अधिकारियों को पहले ही इसकी खबर मिल रही थी, तो फिर क्यों नहीं सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता किया गया? एक हमला हो गया तब जाकर आपातकाल लगाया गया. श्रीलंका में लंबे समय के गृहयुद्ध के बाद शांति स्थापित हुई थी, जिसे फिर किसी की नजर लग गयी. उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार कड़े कदम उठाते हुए निर्दोषों की जान को व्यर्थ नहीं जाने देगी.

शुभम गुप्ता, नावागढ़, धनबाद

काजल को मिले इंसाफ

सभी वेद, उपनिषद्, पुराण साक्षी हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता सुस्थिर होते है. किंतु आज इसी जगतजननी जगदंबा स्वरूपा नारी का घोर अपमान हो रहा है. दहेज उत्पीड़न,भ्रूण हत्या जैसे घृणित कार्य भी इन्हीं के साथ हो रहा है. ताजा मामला भागलपुर अलीगंज की 12वीं की छात्रा काजल के ऊपर तेजाब फेंकने का है. उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु हवन-पूजन का दौर जारी है. याद रखें इस तरह के मामले जिस देश व समाज में हो रहे हैं, वह कभी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता. आज मातृत्व शक्ति के अभाव के कारण ही देश व समाज का विकास अवरुद्ध हो गया है. आवश्यकता है कि काजल को इंसाफ मिले. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह के घृणित कार्य करने के पूर्व एक बार सोचें. तभी हमारे समाज व देश में बदलाव हो सकता है.

नयन तिवारी, चन्नों, कहलगांव

नस्लभेद का विकृत चेहरा!

दुनिया जब शांति पाठ में मशगूल थी, श्रीलंका में नापाक मंसूबे लिए आतंकियों का तांडव चल रहा था. संसार को कष्टभोग से मुक्त कराने वाले 'येशु' के पुनर्जन्म को कुछ पापियों ने कलंकित कर दिया है. नफरत से भरी दुनिया में जाने कब और कौन किसके खून का प्यासा बन जाये. जरूरी नहीं बंदूक उठाने वाला हर शख्स कसूरवार हो. वह तो मोहरा है उस सियासत का जो दुनिया पर काबिज होने के हर घिनौने हथकंडे आजमाती है. बारूदों का सौदागर हो या नस्लभेद का विकृत चेहरा, हर बार हत्या इंसानियत की हुई है. गमों के दो बूंद और आह के दो लफ्ज, नफरत की दीवार तोड़ने के लिए नाकाफी हैं. कत्लेआम के डरावने खेल में किसी एक व्यक्ति, एक मजहब या एक मुल्क को दोषी मान कर खामोश बैठना कायरता है. मजहबी और नस्ली सियासत के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट हो कर आवाज बुलंद करनी होगी.

एमके मिश्रा, रातू, रांची

बोधि वृक्ष

ब्रह्मवाक्य

भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने उस वरदान का प्रयोग भी किया. आप सबने महाभारत में यह कहानी पढ़ी होगी. भीष्म पितामह ने रणभूमि में गिरने के बाद भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की. उनकी संकल्प शक्ति कितनी जबरदस्त रही होगी कि शरीर से पूरा लहू निकल चुका था, फिर भी वे जीवित थे और सामान्य रूप से बातचीत भी कर रहे थे. हमारी पुरातन गाथाओं में ऐसे और भी कई लोगों का नाम आता है, जिन्हें इच्छा मृत्यु या आत्मा को शरीर से अलग करने की क्षमता प्राप्त थी. आदि शंकराचार्य में भी यह क्षमता थी, जिससे उन्होंने परकाया प्रवेश किया. भारत में और भी ऐसे सिद्ध-महात्मा थे, जिनकी अनेक प्रकार की उपलब्धियां रही हैं, लेकिन इन उपलब्धियों को समाज में चमत्कार के रूप में प्रदर्शित न करके उन्होंने इन उपलब्धियों का एक आध्यात्मिक संपदा के रूप में संरक्षण किया, उसे अपने जीवन में उन्नत किया, विकसित किया. लोग कहते हैं कि गुरु का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में ले जाये. एक परिभाषा के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविकता में कभी ऐसा होता नहीं है. ज्ञान तो कोई भी एक घंटा प्रवचन देकर दे सकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि हमने उस ज्ञान को कितना ग्रहण किया. क्या हम अपने जीवन में उस ज्ञान या शिक्षा को जीते हैं? इतने सालों में मेरा अनुभव तो यही रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उस शिक्षा को नहीं जीता है. न संन्यासी, न गृहस्थ. सब अपनी महत्वाकांक्षा को जीते हैं. करोड़ों में शायद कोई एक-आध माई का लाल होता है, जो गुरु की शिक्षाओं को जीता है और उन्हें प्रसारित करता है. लेकिन वह करोड़ों में एक है. बाकी सब गुरु से आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को जी नहीं सकते हैं. एक समय जब मनुष्य का स्वभाव अलग था, तब लोग गुरु की शिक्षाओं पर चलने के लिए मरते थे. उस समय गुरु का एक वाक्य ही व्यक्ति के लिए ब्रह्मवाक्य होता था. अब गुरु का वाक्य ब्रह्मवाक्य नहीं रहा. **स्वामी निरंजनानंद सरस्वती**

कुछ अलग

घरों में किताबों के लिए जगह

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

तीन कमरों का घर. एक कमरे में नीचे से ऊपर तक बड़ी-बड़ी अलमारियां. उनमें सालों पुरानी बेहतरीन किताबें. किताबें और पत्र-पत्रिकाएं अब भी निरंतर आ रही हैं. हालत यह है कि एक नयी किताब तब तक नहीं रखी जा सकती, जब तक कि दो पुरानी न निकाली जायें. हर किताब को देखकर लगता है कि अरे यह तो कभी भी काम आ सकती है. लेकिन अलमारियों की अपनी सीमा है.

मेरे घर के पास ही एक स्कूल है. उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो बस बच्चों के लिए लिखी गयीं कविताओं और नाटकों की किताबें ही चाहिए. कविताएं भी ऐसी जो राष्ट्रीय पर्वों, नेताओं और त्योहारों पर लिखी गयी हों, जो गायी भी जा सकें. फिर मैंने एक बड़े पुस्तकालय के अधिकारी से पूछा. वे कहने लगे कि आपको किताबों की जरूरत हो, तो हमारे यहां से ही ले जाइये, हमने खुद बहुत सी किताबें निकाली हैं.

उनकी बात सुनकर बहुत साल पुरानी एक घटना याद आ गयी. एक मशहूर पुस्तकालय ने एक बार कहा था कि वे बहुत सी किताबें हटाना चाहते हैं. एक बार आकर देख लूं. वहां पहुंचकर जब उनसे किताबों की सूची मांगी, तो वे एक विशाल तहखाने में ले गये. वहां हजारों किताबें थीं, पुरानेपन की गंध से छींकें आने लगीं. उन्हें निकालकर देखना तो संभव ही नहीं था. इनमें से बहुत सी दुर्लभ किताबें रही होंगी. और बहुत सी किताबों का पहला संस्करण ही छपा होगा, जो फिर कभी न मिले. लेकिन हो भी क्या सकता था, किताबों के उस पहाड़ से किताब छांटना तो दूर, उनके पास भी नहीं जाया जा सकता था. दूर खड़े होके भी धूल से तबियत बिगड़ रही थी.

इन दिनों अगर किसी युवा से कहें कि कुछ किताबें चाहिए, तो उसका पहला जवाब तो यही होता है कि अरे टाइम ही कहां है. सवेरे निकलते हैं, रात गये लौटते हैं, फिर भी काम पूरे नहीं होते. किताबें कब पढ़ें? जिनके पास पढ़ने का थोड़ा-बहुत समय है, वे भी ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं. कई कहते हैं कि उन्हें जरूरत की कुछ किताबें घर में रखना पसंद है, पर उनकी साफ-सफाई-देखभाल की फुरसत नहीं है.

एक मित्र अपने गांव में पुस्तकालय चलाते हैं. उन्होंने बताया कि वह कुछ किताबें वहां के लिए खरीद कर लाये थे. एक बार रास्ते में पड़ोस में रहनेवाली दो लड़कियां मिल गयीं. मित्र ने उनसे पूछा- किताबें चाहिए पढ़ने के लिए? लड़कियां दूर भागती बोलीं- नहीं अंकल. अभी तो इम्तिहान खत्म हुए हैं. कुछ दिन तो आराम से रहने दीजिये. लड़कियों की यह प्रतिक्रिया सुनकर मित्र हैरान नहीं हुए. बहुत से बच्चों के लिए किताबें पढ़ने का मतलब, पाठ्यक्रमों में तय हुई किताबें पढ़ना ही रह गया है. हां, हमारे मध्यवर्गीय घरों में किताबों के अलावा साज-सज्जा का बहुत सा सामान जरूर मिलता है.

जो लोग किताबों को बहुमूल्य मानते हैं, वे उन्हें किसी दोस्त की तरह समझते हैं, उनसे तरह-तरह की बातें सीखते हैं. उनकी भी मुश्किल है, घर छोटे हैं और किताबें ज्यादा. बहरहाल, कल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस था.

देश दुनिया से

आतंकवाद से लड़ने में एससीओ की भूमिका

ईस्टर संडे पर श्रीलंका के होटलों और चर्चों में हुए बम विस्फोट के बाद ऐसा लगता है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एशियाई देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है. इसके लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की भूमिका भी बढ़ाये जाने की जरूरत है. श्रीलंका सरकार का मानना है कि हिंसा के पीछे स्थानीय इस्लामिक चरमपंथी समूह, नेशनल तौहीत जमात का हाथ है. श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ वह सभी एशियाई देशों के लिए एक चेतावनी है. चीन खुद आतंकवाद का शिकार है. दक्षिण पूर्व एशिया में, सिंगापुर को आईएस के लड़ाकों ने निशाना बनाया था, जबकि मलेशिया स्थानीय लोगों में बढ़ती कट्टरता से जूझ रहा है. मध्य एशियाई देश लंबे समय से आतंकवाद को सीमा पार से अंजाम दी जाने वाली घटना के रूप में देखते आये हैं. और दक्षिण में भारत और पाकिस्तान भी आतंकी हमलों के शिकार होते रहते हैं. इसी कारण सभी एशियाई देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है. चीन व भारत ने श्रीलंका को सुरक्षा के लिए सहायता की भी पेशकश की है. इन सहमति के आधार पर यह सही समय है जब क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए एससीओ एक समन्वित प्रणाली स्थापित करे. **वैंग वेनवेन**

GLOBAL TIMES

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है